



[Handwritten signature]

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड ३—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

लं. 458]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 12, 1985/आस्विन 20, 1907

No. 458]

NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 12, 1985/ASVINA 20, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वाली है जिससे कि यह अग्रम संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आधिकारी वार्षीय विभाग)

बीमा

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 1985

अधिसूचना

भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी 1 अधिकारी

(सेवा के निवधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985

मा० का० नि० 794(म) ---केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम
अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपषारा (2) के लंबे
(गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा
निगम के श्रेणी 1 के अधिकारियों (प्रबन्ध नियेशकों से फ़िल) की सेवा
के क्षतिपूर्ण निवधनों और शर्तों का विनियमम् करने के लिए निम्नलिखित
नियम बनाती है, अधीत :--

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना :-- (1) इन नियमों का
संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम, श्रेणी 1 अधिकारी (सेवा के
निवधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 है।

(2) में 1 अक्टूबर, 1983 को प्रवृत्त हुए समझे जाएँगे।

(3) ये नियम, जब तक कि किसी संविधान के निवधनों द्वारा
अन्यथा उपबंधित न हो, भारत में निगम के प्रत्येक पूर्णकालिक (वेतन-
भोगी) श्रेणी 1 अधिकारी को लागू होंगे।

(4) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी, राजपत्र में
इन नियमों के प्रकाशित होने की तारीख से तीस विन के भीतर यदि
कोई श्रेणी 1 अधिकारी निगम को लिखित सूचना देता है, जिसमें वह
इन नियमों के देशे प्रकाशन की तारीख से उसके उपबन्धों से शासित
होने का अपना विकल्प अभियक्ष करता है, तो निगम, आदेश द्वारा,
ऐसे अधिकारी को उक्त तारीख से उक्त नियमों द्वारा शासित होने
की अनुशा दे सकता है।

2. परिभाषाएँ :-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा
अपेक्षित न हो :--

(क) "अधिनियम" से जीवन बीमा अधिनियम, 1956 (1956 का
31) अनुप्रीत है:

(ल) "श्रेणी 1 अधिकारी" से भारतीय जीवन बीमा निगम का
(प्रबन्ध नियेशकों से भिन्न) श्रेणी 1 पद पर कार्य

कर रहा का कर्मचारी अभिप्रेत है और इसके अलांकृत वह व्यक्ति भी है जो अधिकारियम के अधीन, सियत विन को, ऐसा कर्मचारी हो गया है और इस रूप में कार्य कर रहा है;

(ग) "कर्मचारी वृद्ध" विनियम, से मारतीय जीनन बीमा निगम (कर्मचारी वृद्ध) विनियम, 1960 अभिप्रेत है;

(घ) ऐसे यदों और पदों का जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभासित नहीं है, किन्तु जो कर्मचारी वृद्ध विनियमों में परिभासित है वही अर्थ है जो कर्मचारी वृद्ध विनियम में है।

3. श्रेणी 1 के अधिकारियों की सेवा की गते :- कर्मचारी वृद्ध विनियम में किसी बात के हाते द्वारा जो इन नियमों में सम्मिलित विषयों के सम्बन्ध में श्रेणी 1 के अधिकारियों की सेवा के निष्पत्तन और गते इन नियमों में इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार विनियमित होती।

4. श्रेणी 1 अधिकारियों के बेतनमान :- श्रेणी 1 अधिकारियों के बेतनमान निम्नलिखित होते :-
श्रेणी 1 अधिकारी :

1. (i) भेदीय प्रबन्धक/केन्द्रीय कार्यालय में विभागों के प्रमुख।	(क) सामान्य बेतनमान :
	3725-125-4350 रु
(ii) मुख्य इंजीनियर/मुख्य वास्तुविद्	(ख) जथन बेतनमान
	4100-125-4600 रु

टिप्पणी :

- (1) केन्द्रीय कार्यालय में किसी विभाग के भारताधिक के रूप में पश्चय घयन बेतनमान के अधिकारी कार्यकारी निवेशक के रूप में पदभित्र होते हैं।
- (2) यद्यपि सामान्यतया केन्द्रीय कार्यालय में विभागों के प्रमुख, केन्द्रीय प्रबन्धकों के काडर में से यिहे जाएंगे तथा वही इस काडर में इन पदों की भरने हेतु उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हों वहाँ उन्हें उप भेदीय प्रबन्धकों/वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धकों और केन्द्रीय कार्यालय के मणियों/बीमांकों/लेखाकारों के काडर में से लिया जा सकेगा तथा उन्हें प्रमुख भारताधिक के रूप में पदभित्र किया जाएगा।

2. (i) उप भेदीय प्रबन्धक/ वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक और केन्द्रीय कार्यालय के सचिव/ बीमांकक/लेखाकार।	{	श्रेणी 1 अधिकारी के लिए जो रु 1600/- से अधिक मूल बेतन प्राप्त कर रहा है, सूचकांक के तैमासिक औसत में 332 अंकों के ऊपर प्रत्येक आठ अंकों के लिए अधिक से अधिक 31.60 रु तक (जिसे इसके पश्चात "सूचकांक" कहा गया है)
(ii) उप मुख्य इंजीनियर/ उप मुख्य वास्तुविद्।		3245-110-3685-115-3800 रु
3. (i) मण्डल प्रबन्धक और भेदीय कार्यालयों के सचिव/ बीमांकक/लेखाकार/किन्तीय कार्यालय के उप सचिव (लेखापरीका और निरीकण)/ उप सचिव/उप बीमांकक/ उप लेखाकार।		
(ii) अधीकारण इंजीनियर/ वरिष्ठ कार्य सर्वेक्षक/ वरिष्ठ वास्तुविद्।		2715-105-3450 रु

4. (i) सहायक मण्डल प्रबन्धक/वरिष्ठ पालाका प्रबन्धक और केन्द्रीय तथा	{
---	---

श्रेणीय कार्यालय के सहायक सचिव/सहायक बीमांकक/सहायक लेखाकार।
(ii) कार्यपालक इंजीनियर/
कार्य सर्वेक्षक/उप वरिष्ठ वास्तुविद्।

2250-100-3250 रु

5. (i) गाला प्रबन्धक/
प्रशासनिक अधिकारी
(ii) सहायक कार्यपालक
इंजीनियर/सहायक
कार्य सर्वेक्षक/आगुनिद

1625-100-2925 रु

6. (i) महायक गाला प्रबन्धक
सहायक प्रशासन-
अधिकारी
(ii) महायक इंजीनियर/
सहायक वास्तुविद्।

1175-75-1400-85-2675 रु

टिप्पणी :- विभिन्न क्रम संख्याओं के अन्वर्गत प्रविष्ट (2) में विनियमित पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों के सम्बन्ध में पृष्ठ वरिष्ठता सूची यद्यों जाएगी।

5. मंहगाई भत्ता :

(1) श्रेणी 1 अधिकारियों को लाग भत्ते का मापमान निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाएगा :-

(क) सूचकांक : अधिकम भारतीय कर्मकार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात "सूचकांक" कहा गया है)

(ख) अधार : 1960 की श्रृंखला में सूचकांक सं० 332-100,

(ग) दर : सूचकांक तैमासिक औसत में 332 अंकों के ऊपर प्रत्येक आठ अंकों के लिए मूल बेतन का 2 प्रतिशत, किन्तु प्रत्येक आठ अंकों के लिए अधिक से अधिक 31.60 रु तक (जिसे इसमें इसके पश्चात "विनियमित दर" कहा गया है)।

(2) विनियमित वर्ग पर देय मंहगाई भत्ते का ऊपर की ओर पुनरीक्षण निम्न प्रकार में किया जाएगा--

(1) प्रत्येक श्रेणी I अधिकारी के लिए जो रु 1600/- से अधिक मूल बेतन प्राप्त कर रहा है, सूचकांक के तैमासिक औसत में 332 अंकों के ऊपर प्रत्येक आठ अंकों की वृद्धि के लिए 332-340-348-356-364-372-380-388-396-404 के क्रम में तथा इसी प्रकार आगे के क्रम में; तथा

(2) रु 1601 रु और उससे अधिक किन्तु 2425 रु से अधिक के मूल बेतन पाने वाले श्रेणी I अधिकारियों के लिए सूचकांक के तैमासिक औसत में 332 अंकों के ऊपर 24 अंकों के बीच में तथा सूचकांक के तैमासिक औसत के अगले 8 अंकों की वृद्धि के लिए 332-348-356-364-372-380-396-404 के क्रम में तथा इसी प्रकार आगे के क्रम में; तथा

(3) 2426 रु तथा उससे अधिक मूल बेतन पाने वाले श्रेणी I अधिकारियों के लिए सूचकांक के तैमासिक औसत में 332 अंकों के ऊपर प्रत्येक 24 अंकों की वृद्धि के लिए 332-348-356-380-396-404 तथा इसी प्रकार आगे के क्रम में; तथा

(3) उप नियम (1) या उप नियम (2) में किसी बात के होने द्वारा भी—

(क) सूचकांक के तैमासिक औसत में प्रत्येक 24 विन्दुओं के क्रम की वृद्धि के लिए मूल बेतन के इसी भी अनुक्रम पर देय मंह-

गाई-भला मूल वेतन के 3.9 प्रतिशत की दर पर देय मंहगाई भत्ते से 150 रु. से जो भी कम है, कम नहीं होगा; और

(अ) यदि किस ममय उप नियम (2) के अनुमार देय मंहगाई-भत्ता मूल वेतन के किस भ. प्रतिक्रम निम्नवर मूल वेतन के लिए प्रत्येक मंहगाई भत्ते से कम है तो सुलगत उच्चतर अनुक्रम पर देय मंहगाई भला निम्नवर मूल वेतन पर देय मंहगाई भत्ते के बराबर होगा।

(4) (क) श्रेणी I प्रधिकारियों का देय मंहगाई-भत्ते का मूल वेतन क. संबंधित शृंखलाओं में न.चे क. भी और पूर्वक्रम होगा यदि सूचकांक का दैमानिक श्रीमत (जिसे इसमें इसके पश्चात "चालू श्रीमत अंक" कहा गया है) उप नियम (2) में निर्दिष्ट संबंधित कम में उस सूचकांक के न.चे गिर जाता है, जिसके प्रति निर्देश से अतिम पूर्ववर्ती लैमाम के लिए मंहगाई भत्ते का सदाय किया गया है।

(ब) न.चे क. और पूर्वक्रम होने पर, देय मंहगाई-भत्ता चालू श्रीमत अंकों के तत्समान होगा यदि ऐसा चालू श्रीमत अंक सुलगत शृंखला में एक अंक है; तथा देय मंहगाई-भत्ता सुलगत शृंखला में चालू श्रीमत अंक के ठंके प्रगाम अंक के तत्समान होगा यदि ऐसा चालू श्रीमत अंक शृंखला में एक अंक मही है।

6. मकान किराया भत्ता.—(1) श्रेणी I प्रधिकारियों की उनके विवाह जिन्हे स्टाफ क्वार्टर प्रारंभित किया गया है मकान किराया भत्ता मूल वेतन के 15% का दर से लागू होगा, किन्तु यह कम है कम 200 रु. तथा प्रधिकरण 400 रु. होगा।

(2) ऐसे श्रेणी I प्रधिकारि किसे स्टाफ क्वार्टर प्रारंभित किया गया है किस मकान किराया भत्ते के हक्कदार नहीं होते, किन्तु वे उन्हें प्रारंभित स्टाफ क्वार्टर के लिए मूल वेतन के 10 प्रतिशत या समुचित अनुकूलित मूल के समतुल्य रकम का, दोनों में जो भी कम है, संदेश करेंगे।

7. नगर प्रतिपुरक भत्ता:—श्रेणी I के प्रधिकारियों का देय नगर प्रतिपुरक भत्ता यह होगा:—

(क) श्रेणी I के प्रधिकारि जो 12 लाख से प्रधिक आवाद वाले नगरों में निवास करते हैं तथा मासिकोंवा के नगर व ज़िलों में पदाधि है, मूल वेतन का 10 प्रतिशत, किन्तु प्रधिक से प्रधिक 300 रु. प्रति माह, तथा

(ब) श्रेणी I के प्रधिकारि जो उन नगरों में, जिनके आवाद 5 लाख तथा उससे अधिक किन्तु 12 लाख से कम है तथा राज्यों के राजधानीयों में जिनको आवाद 12 लाख से अधिक नहीं है और वहाँ गढ़ पाइडिंसरे तथा पोर्ट एंड एंडर में पदाधि है। मूल वेतन का 6 प्रतिशत किन्तु 120 रु. प्रधिक से प्रधिक प्रतिमाह।

स्पष्ट करण: इस नियम के प्रयोगन के लिये, 1981 का जनगणना क. रिपोर्ट में दिए गए प्रावाद, के आंकड़े गणना में किए जाएंगे।

8. भविष्य निधि:—परिवेशाधिन प्रधिकरण या प्रस्ताव, प्राथार पर नियुक्त किए गए प्रधिकारीयों किसी भन्नोवित प्रधिकरिता निधि में प्रधिदाय कर रहे प्रधिकारी से मिल प्रत्येक श्रेणी I प्रधिकारि नियम द्वारा स्पष्ट भविष्य निधि में प्रपने मूल वेतन का 8-1/3 प्रतिशत का दर से प्रधिदाय करेगा। प्रावाद नियम भी भविष्य निधि में प्रतिमास प्रत्येक प्रधिकारि द्वारा वस्तुतः प्रधिकरण या वास्तविक प्रधिकरण के वरावर रकम का सविष्य निधि में प्रधिदाय ऐसे प्रत्येक प्रधिकारि के मूल वेतन का प्रधिक से अधिक 8-1/3 प्रतिशत तक, करेगा।

(2) प्रोट्रियाटन गवर्नमेन्ट मिनिस्टरी लाइफ एंड रेस कम्पनी लिमिटेड के स्थानान्तरित श्रेणी I प्रधिकारि और जो उस कम्पनी

की वेश्वन निधि में प्रधिदाय कर रहे हैं, जिने केवल ऐसे कर्मचारियों के लिए एक दृष्टक निधि के रूप में, उपन्तरकों सहित जारी रखा जा रहा है, उस निधि के नियमों के अनुसार वेतन के हक्कदार होते।

(3) तथापि उपनियम (2) में निर्दिष्ट श्रेणी I के प्रधिकारियों नियम द्वारा स्पष्टित भविष्य निधि में प्रधिदाय करने के लिए अनुशासित कि जो सकते हैं परन्तु ऐसे कर्मचारियों का वावत प्रधिष्य निधि में नियम में कोई प्रधिदाय करने का अपेक्षा नहीं होता।

9. उपदान: (1) (क) ऐसा स्थाय श्रेणी I प्रधिकारि जो परन्तु वर्ष से अन्यत वर्षों तक (जिसमें 1 सितम्बर, 1956 को या उसके पश्चात भर्ती किए गए कर्मचारियों का वावत परिवर्का की या प्रस्ताव, ये वा का प्रवधि सम्मिलित नहीं का जाएगी) नियम का निरन्तर ये वा में (जिसमें ब.माकर्ता के पास नियमित वैतनिक ये वा भी सम्मिलित है) रहा है, और:

(1) जिसके ये वा में नियम द्वारा किसी भ. कारण से समाप्त कर दी जाती है, या

(2) जो स्वेच्छा में नियम क. सेवा से त्यागपत्र देना है, या

(3) स्थाय श्रेणी I प्रधिकारि:—

(i) जिसका नियम की सेवा क. में रहते हुए मत्तु हो जाता है, या

(ii) जो नियम क. ये वा में नियूत होता है, या

(iii) जिसके सेवाएं या तो निरन्तर व मार के कारण या किल उस दुर्घटना के कारण जिससे वह अपने कर्तव्यों के निर्वाह में असमर्थ हो जाता है, समाप्त कर दी जाता है; या

(4) जिसके ये वा में कर्मचार वृद्ध में कम होने का राज्य के संस्थापन के पूर्वांगन के कारण समाप्त कर दी जाती है; या

उपदान के मदाय के लिए पाव होता।

(2) श्रेणी I के प्रधिकारि को उपनियम (1) के प्रधन अनुलेप्य उपदान, निरन्तर ये वा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए (जिसमें ब.माकर्ता के पास नियमित वैतनिक ये वा भी सम्मिलित है) एक मास के वैतनिक मूल वेतन की दर से देय होता किन्तु वह 30 वर्ष की ये वा तक प्रधिकरण 15 मास के मूल वेतन तथा तथा 30 वर्ष से प्रधिक का ये वा के लिए ये वा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह मास में प्रधिक के भाग के लिए ये वा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष या छह मास में प्रधिक के भाग के लिए ये वा का वैतन होता।

परन्तु ऐसे प्रधिकारि द्वारा प्रपने ये वा का पूर्ण प्रधिष्य के बीचार 12 मास से प्रधिक के अवधि तक प्रमाणाचारण द्वाटा पर बिताई गई अवधि प्रधिष्यत कर दी जाएगी।

(3) ऐसे श्रेणी I प्रधिकारि की दशा में जिसे श्रेणी 3 के कानून में पहले अप्रैल, 1973 को अवधि उसके पश्चात प्रोत्तत किया गया, तथा जिसका मत्तु या ये वा नियूत प्रोत्तत के पश्चात हो जाता है, उसको देय उपदान उस उपदान से कम नहीं होता जो उसको उस स्थिति में देय होता है यदि उसको ये वा तब समाप्त कर दी जाती जब वह श्रेणी 3 के कानून में या।

(4) श्रेणी I के प्रधिकारि को अनुलेप्य उपदान का रकम पर नियम को प्राप्त किसी वास्तविकार के प्रधन वर्ष से हुए नियम, प्रधिकारि को, या उसके भाग निर्देशित या नामनिर्देशित यो को, या यदि कोई नामनिर्देशित नहीं किया गया है या विद्यमान नहीं है तो प्रधिकारि के उत्तराधिकारियों को इस नियम के वैतन प्रत्येक उपदान का रकम का संवाद करेगा।

(5) उपर के उपनियमों में अन्तर्विष्ट किसी वात के होते हुए भी:-

(1) जहाँ श्रेणी 1 के कानून प्रधिकार पर प्रबन्धालय या प्रध्य कर्मचारियों के विवर हिस्से में अन्तर्विष्ट किसी कानून के विवर या नियोजन के स्थान में या उसके विवर किसी वास्तविक

विशेषज्ञ व्यवहार के लिए परम्परागत का शास्ति प्रधिरोपित का जाती है, वहाँ उसे देय उपचान पूर्णतः समरूप हो जाएगा; और

(2) जहाँ ऐसों I के किसी प्रधिकार पर अनिवार्य ऐसा निवृत्ति, ऐसा ये हटाए जाने या परम्परागत का शास्ति उसके किस ऐसे कार्य के लिए जिसमें नियम को वित्तीय हानि सहन पड़े, प्रधिरोपित का जाता है वहाँ उसको देय उपचान से उतनः रकम समरूप हो जाएगा, जितना हानि हुई है।

10 निर्विचान :— यदि इन नियमों के निर्विचान के सम्बन्ध में कोई घंटा या कठिनाई उत्पन्न होता है तो उसे विनियोग के लिए केन्द्रीय सरकार को निविष्ट किया जाएगा।

[फा. सं. 2 (6)/वा. III/85]
ए. सं. येत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Insurance

New Delhi, the 11th October, 1985

NOTIFICATION

Life Insurance Corporation of India Class I Officers
(Revision of Terms and Conditions of Service) Rules,
1985

GSR 794 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (cc) of sub-section (2) of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules regulating certain terms and conditions of service of Class I Officers (other than the Managing Directors) of the Life Insurance Corporation of India, namely:—

1. Short title, commencement and application:—
(1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India, Class I Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of October, 1983.

(3) They shall apply to every whole-time (salaried) Class I Officer of the Corporation in India unless otherwise provided by the terms of any contract.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), Where any Class I Officer gives a notice in writing to the Corporation, within thirty days of the date of publication of these rules in the Official Gazette, expressing his option to be governed by the provisions of these rules with effect from the date of such publication, then the Corporation may, by order, permit such officer to be governed by the said rules with effect from the said date.

2. Definitions:—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956);

(b) "Class I Officer" means an employee of the Life Insurance Corporation of India (other than the Managing Directors) working in Class I post and includes any person who became an employee of Corporation on the appointed day under the Act and is so working;

(c) "Staff Rules" means the Life Insurance Corporation of India (Staff) Regulations, 1960;

(d) words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Staff Rules, shall have the meanings respectively assigned to them in the Staff Rules.

3. Conditions of Service of Class I Officers: Notwithstanding anything contained in the Staff Rules, the terms and conditions of service of Class I Officers relating to matters covered by these rules shall be regulated in accordance with the provisions hereinafter contained in these rules.

4. Scales of pay of Class I Officers: The scales of pay of Class I Officers shall be as under:—

Class I Officers:

1. (i) Zonal Managers/Chiefs of Departments at Central Office.	(a) Ordinary Scale: Rs.3725-125-4350
(ii) Chief Engineer/Chief Architect.	(b) Selection Scale: Rs.4100-125-4600

Notes (1) Officers in selection scale posted in-charge of a Department at the Central Office will be designated as Executive Directors.

(2) While Chiefs of Departments at Central Office would normally be drawn from the cadres of Zonal Managers, where suitable officers for filling up these posts are not available from this cadre they may be drawn from the cadre of Deputy Zonal Managers/Senior Divisional Managers/Secretaries/Actuaries/Accountants at Central Office and they will be designated as Chief-in-Charge.

2.	(i) Deputy Zonal Manager/ Senior Divisional Managers and Secretaries/ Actuaries/ Accountants at the Central Office. (ii) Deputy Chief Engineers/ Deputy Chief Architects.	Rs.3245-110-3685- 115-3800.	(ii) Assistant Executive Engineers/ Assistant Surveyors of Works/ Architects.
			6. (i) Assistant Branch Managers/ Assistant Administrative Officers. (ii) Assistant Engineers/- Assistant Architects.
3.	(i) Divisional Managers and Secretaries/ Actuaries/ Accountants at the Zonal Offices/Deputy Secretaries (A&I) Deputy Secretaries Deputy Actuaries/- Deputy Accountants at the Central Office. (ii) Superintending Engineers/ Senior Suive- yors of Works/ Senior Architects.	Rs.2715-105-3450.	6. (i) Assistant Branch Managers/ Assistant Administrative Officers. (ii) Assistant Engineers/- Assistant Architects.
			Rs.1175-75-1400-85- 2675
4	(i) Assistant Divisional Managers/ Senior Branch Managers and Assistant Secretaries/ Assistant Actuaries/ Assistant Accountants at the Central Office and Zonal Office. (ii) Executive Engineers/ Surveyors of Works/Deputy Senior Architects.	Rs.2250-100-3250	Note: A separate seniority list shall be maintained in respect of Officers appointed to posts specified in entry (ii) under various serial numbers.
			5. Dearness Allowance: (1) The scales of dear- ness allowance applicable to Class I Officers shall be determined as under:— (a) Index: All India Working Class Consumer Price Index (hereinafter referred to as the "Index") (b) Base: Index No. 332 in the series 1960—100; (c) Rate: 2 per cent of the basic pay for every eight points in the quarterly average of the Index above 332 points, sub- ject to a maximum of Rs. 31.60 for every 8 points (hereinafter referred to as the "specified rate"). (2) There shall be an upward revision of the dearness allowance payable at the specified rate,— (i) for every eight points rise in the quarterly average of the Index above 332 points in the sequence 332-340-348-356-364-372-380-388- 396-404 and so on, for Class I Officers drawing a basic pay of not more than Rs. 1600/-; (ii) for the first sixteen points rise in the quar- terly average of the Index in a cycle of 24 points rise above 332 points and for the next eight points rise in the quarterly average of the Index in the sequence 332-348-356-372- 380-396-404 and so on, for Class I Officers drawing a basic pay of Rs. 1601 and above but not more than Rs. 2425/- and (iii) for every twenty four points rise in the quarterly average in the Index above 332 points in the sequence 332-356-380-404 and
5.	(i) Branch Managers/ Administrative Officers.	Rs. 1625-100-2725	

so on, for those Class I Officers drawing a basic pay of Rs. 2426/- and above.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) or sub-rule (2),—

(a) the dearness allowance payable at any stage of basic pay for each cycle of 24 points rise in the quarterly average of the Index shall not be less than the dearness allowance payable at the rate of 3.9 per cent of the basic pay or Rs. 150/- whichever is less; and

(b) if at any time the dearness allowance payable in accordance with sub-rule (2) at any stage of basic pay is less than that admissible for a lower basic pay, the dearness allowance payable at the relevant higher stage shall be equal to that payable for the lower basic pay.

(4) (a) There shall be downward revision of the dearness allowance payable to Class I Officers in the respective ranges of basic pay if the quarterly average of the index (hereinafter referred to as the "current average figure") falls below the index figure in the respective sequences referred to in sub-rule (2) with reference to which the dearness allowance has been paid for the last preceding quarter.

(b) On the downward revision, the dearness allowance payable shall correspond to the current average figure if such current average figure is a figure in the relevant sequence; and the dearness allowance payable shall correspond to the figure in the relevant sequence next preceding the current average figure if such current average figure is not a figure in the sequence.

6. House Rent Allowance:—(1) The scales of house rent allowance applicable to Class I Officers, except those who have been allotted staff quarters, shall be at the rate of 15 per cent of the basic pay, subject to a minimum of Rs. 200/- and a maximum of Rs. 400/-.

(2) Class I Officers who are allotted staff quarters, shall not be entitled to any house rent allowance but they shall pay an amount equivalent to 10 per cent of the basic pay or the appropriate licence fee, whichever is less, for the staff quarters allotted to them.

7. City Compensatory Allowance: The scales of City Compensatory Allowance payable to Class I Officers shall be as under:—

(a) Class I Officers posted in cities with population exceeding 12 lakhs and Urban Agglomeration of Panaji and Mormugoa—10 per cent of basic pay, subject to a maximum of Rs. 200/- per month; and

(b) Class I Officers posted in cities with a population on 5 lakhs and above but not exceeding 12 lakhs, State Capitals with population not exceeding 12 lakhs and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair—6 per cent of basic pay, subject to a maximum of Rs. 120 per month.

Explanation:—For the purposes of this rule, the population figures as reported in the 1981 Census Report shall be taken into account.

8. Provident Fund: (1) Every Class I Officer of the Corporation, other than an Officer on probation or an officer appointed on temporary basis or an officer who is contributing to an approved Superannuation Fund, shall contribute to the Provident Fund established by the Corporation at the rate of 8 1/3 per cent of his basic pay and the Corporation shall also contribute to the Provident Fund every month an amount equal to the actual contribution of each such officer subject to a maximum of 8 1/3 per cent of the basic pay of each such officer.

(2) Class I Officers who are transferred employees of the Oriental Government Security Life Assurance Company Ltd., and who are contributing to the Pension Fund of that Company, which is being continued with modifications as a separate Fund for such employees only, shall be entitled to pension according to the rules of that Fund.

(3) Class I Officers referred to in sub-rule (2) may, however, be permitted to contribute to the Provident Fund established by the Corporation but the Corporation shall not be required to make any contribution to the Provident Fund in respect of such officers.

9. Gratuity: (1) (a) A permanent Class I Officer who has been in continuous service of the Corporation (including regular salaried service with the insurer for not less than 15 years (excluding period of probation or temporary service in respect of employees recruited on or after the 1st September, 1956); and—

(i) whose services are terminated by the Corporation for any reason whatsoever; or

(ii) who voluntarily resigns from the service of the Corporation;

or

(b) a permanent Class I Officers

(i) who dies while in the service of the Corporation;

or

(ii) who retires from the service of the Corporation;

or

(iii) whose services are determined either due to continued illness or accident incapacitating him from the proper discharge of his duties;

or

(iv) whose services are dispensed with owing to reduction of staff or reorganisation of establishment;

shall be eligible for the payment of gratuity.

(2) The gratuity admissible to a Class I Officer under sub-rule (1) shall be at the rate of one month's terminal basic pay for each completed year of continuous service or part thereof in excess of six months (inclusive of regular salaried service with the insurer) subject to a maximum of 15 months' basic pay upto 30 years of service, and for service over 30 years, half-a-month's terminal basic pay for each completed year of service or part thereof in excess of six months:

Provided that any period spent by such officer on extraordinary leave exceeding 12 months during the entire period of his service shall be excluded.

(3) In the case of a Class I Officer who has been promoted from Class III cadre on or after the 1st day of April, 1973 and who dies or retires after promotion, the Gratuity payable to him shall not be less than the gratuity that would have been payable to him if his services had been terminated while he was in Class III cadre.

(4) Subject to any lien the Corporation may have on the amount of gratuity admissible to a Class I Officer, the Corporation shall pay the Officer or his nominee or nominees or if no nomination is made or is subsisting, his heirs, the amount of gratuity admissible under this rule.

(b) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-rules—

(i) where the penalty of dismissal is imposed on a Class I Officer for any act involving violence against the management or other employees or any riotous or disorderly behaviour in or near the place of employment, the gratuity payable to him shall stand wholly forfeited;

and

(ii) where the penalty of compulsory retirement removal from service or dismissal is imposed on a Class I Officer for any act involving the Corporation in financial loss, the gratuity payable to him shall stand forfeited to the extent of such loss.

10. Interpretation: Where any doubt or difficulty arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for its decision.

[F.No.2(6)/Ins.III/85]
A.C. SEN, Jt. Secy.

